भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
23.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 639 का उत्तर

अंगमाली-एरुमेली-सबरी रेलवे लाइन

639. श्री बैन्नी बेहनन:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री एंटो एनटोनी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार अंगमाली-सबरीमाला रेलवे परियोजना की पूरी लागत वहन करेगी या राज्य की अधिकतम उधार सीमा बढ़ाएगी क्योंकि केरल लागत साझा करने के लिए राज्य की अधिकतम उधार सीमा में वृद्धि की मांग कर रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) केरल और राज्य के सभी सांसदों के अनुरोध पर अंगमाली-एरुमेली, सबरी रेलवे परियोजना को गतिरोध से मुक्त करने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्ष 2005 में अंगमाली-एरूमेली, सबरीमला रेलवे लाइन परियोजना के लिए चिन्हित की गई 70 किलोमीटर लंबी सीमा-पत्थर वाली भूमि पर रेलवे द्वारा भूमि की कीमत वितरित करने की रेलवे की योजना क्या है;
(घ) क्या उन भूस्वामियों को मुआवज़ा देने का कोई निर्णय लिया गया है जिनकी भूमि 2005 में परियोजना के लिए चिह्नित की गई थी;
(ङ) क्या सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रेलवे कार्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(च) क्या सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या सरकार की इस रेलवे लाइन को तिरुवनंतपुरम तक विस्तारित करने और विझिंजम बंदरगाह से जोड़ने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): अंगमालि-सबरीमाला बरास्ता एरुमेली नई लाइन परियोजना को 1997-98 में स्वीकृति दी गई थी। अंगमालि-कालडि (7 कि.मी.) और कालडि-पेरुम्बवूर (10 कि.मी.) पर अधिक समय तक

चलने वाला कार्य शुरू किया गया था। बहरहाल, भूमि अधिग्रहण और लाइन के संरेखण के निर्धारण के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध, परियोजना के खिलाफ दायर अदालती मामलों और केरल राज्य सरकार से अपर्याप्त समर्थन के कारण इस परियोजना पर आगे काम नहीं बढ़ाया जा सका।

परियोजना की अनुमानित लागत को 3801 करोड़ रुपए पर अद्यतन किया गया है और अनुमान की स्वीकृति और परियोजना की लागत साझा करने की इच्छा के लिए दिसंबर, 2023 में केरल सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

अगस्त 2024 में, केरल सरकार ने अपनी सशर्त सहमति प्रदान कर दी है। रेलवे ने केरल सरकार से लागत साझा करने के लिए बिना शर्त सहमति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

केरल सरकार से इस परियोजना के लिए केरल राज्य सरकार, रेल मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का भी अनुरोध किया गया है।

बहरहाल, केरल सरकार द्वारा 3 जून, 2025 को रेल मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में, यह सूचित किया गया है कि केरल सरकार त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं है।

केरल सरकार परियोजना की लागत में अपनी 50% हिस्सेदारी का उपयोग भूमि अधिग्रहण करने पर सहमत हो गई है। एक बार राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू हो जाए, तो कार्य संबंधी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है।

सबरीमाला रेल परियोजना और विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के बीच कोई संबंध नहीं है।

******